वॉल्यूम 34, सं. 1, जुलाई, 2025

इंफोर्मेटिक्स

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा प्रकाशित एवं ई गवर्नेंस बुलेटिन

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

Digital India
Power To Empower

एनआईसी NIC

संपादकीय संयोजन : जी. वेंकू बाई

भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 2 मई, 2025 को राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए पहल - 'सम्मान के साथ वृद्धावस्था' नामक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिक कल्याण पोर्टल (https://scw.dosje.gov.in) का शुभारंभ करती हुई

भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा "एजिंग विद डिग्निटी" पोर्टल का उद्घाटन

भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने वरिष्ठ नागरिक कल्याण पोर्टल (https://scw.dosje.gov.in) का उद्घाटन किया और 02 मई 2025 को राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में अनकापल्ली (आंध्र प्रदेश), तवांग (अरुणाचल प्रदेश), वोखा (नागालैंड), वेल्लोर (तमिलनाडु), नैनीताल (उत्तराखंड) में पांच वरिष्ठ नागरिक गृहों का वर्चुअल उद्घाटन किया। अपने संबोधन में माननीय राष्ट्रपति ने पोर्टल की विशेषताओं और आवश्यक कल्याणकारी योजनाओं और सहायता सेवाओं तक आसान पहुंच की सुविधा प्रदान करके बुजुर्गों को सशक्त बनाने में इसकी भूमिका पर जोर दिया।

पोर्टल को सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) टीम द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है, जो पूरे भारत में वरिष्ठ नागरिकों के लिए सेवाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए एकल-खिड़की मंच के रूप में कार्य करता है। यह पहल भारत के वरिष्ठ नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, यह सुनिश्चित करता है कि उन्हें समय पर सहायता और देखभाल मिले।

उद्घाटन समारोह में कई गणमान्य अतिथि मौजूद थे, जिनमें डॉ. वीरेंद्र कुमार (केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री), श्री रामदास अठावले, श्री बी.एल. वर्मा (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री), और श्री अमित यादव (सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय) तथा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। ब्रह्माकुमारी शिवानी वर्मा और ब्रह्माकुमारी आशा भी मौजूद थीं।

कार्यक्रम के दौरान, केंद्रीय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने वरिष्ठ नागरिकों को महत्वपूर्ण सेवाओं और कल्याणकारी योजनाओं तक सुव्यवस्थित पहुंच प्रदान करके उनके कल्याण को बढ़ाने में पोर्टल की भूमिका पर जोर दिया, जिससे उन्हें सम्मान, सुरक्षा और संतुष्टि का जीवन जीने में मदद मिलेगी।

इस कार्यक्रम में श्री प्रशांत कुमार मित्तल, उप महानिदेशक, श्री आलोक श्रीवास्तव, वरिष्ठ निदेशक (आईटी) और श्री आनंद वर्मा, संयुक्त निदेशक (आईटी) सहित एनआईसी के कई प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे। इस आयोजन में सहयोग प्रदान करने के लिए एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग डिवीजन, एनआईसी राष्ट्रपति भवन टीम और संबंधित राज्य टीम को विशेष धन्यवाद।

- अर्चना शर्मा, एनआईसी मुख्यालय

विश्व पर्यावरण दिवस पर 'दक्षिण केदारन्या' संरक्षण पहल का उद्घाटन

विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में, श्री क्षेत्र ज्योतिर्लिंग डोंगर, कोल्हापुर, महाराष्ट्र के लिए 'दक्षिण केदारन्या' संरक्षण पहल का उद्घाटन 5 जून 2025 को महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फड़नवीस द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया।

इस कार्यक्रम में प्रतीकात्मक वृक्षारोपण अभियान भी चलाया गया, जिसमें पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी ने वर्चुअल माध्यम से की, जिसमें लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री प्रकाश अबितकर और महाराष्ट्र सरकार के चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री हसन मुश्रीफ ने सक्रिय भागीदारी की।

एनआईसी कोल्हापुर जिला केंद्र ने स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए तकनीकी सहायता प्रदान की। एनआईसी मुंबई की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टीम ने राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, महाराष्ट्र के मार्गदर्शन में एनआईसी मुख्यालय वीसी प्रभाग के सहयोग से इस कार्यक्रम का समन्वय किया, जिससे सभी स्थानों पर निर्बाध निष्पादन सुनिश्चित हुआ।

- सुनीता रामकृष्ण नवरे, महाराष्ट्र

महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 'दक्षिण केदारन्या' संरक्षण पहल का उद्घाटन

एनआईसी ने बेलगावी में विजन कर्नाटक 2025 प्रदर्शनी में डिजिटल सशक्तिकरण का प्रदर्शन किया

तीन दिवसीय विज़न कर्नाटक 2025 प्रदर्शनी, जो 11-13 जुलाई तक केएलई सेंटेनरी कन्वेंशन सेंटर, बेलगावी में आयोजित की गई, जिसमें राज्य की विकास यात्रा और डिजिटल भविष्य को प्रदर्शित किया गया। माननीय सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री श्री जगदीश शेट्टार द्वारा उद्घाटन किए गए इस कार्यक्रम में नेताओं, नागरिकों और नवप्रवर्तकों को एक छत के नीचे एक साथ लाया गया।

प्रदर्शनी का मुख्य आकर्षण एनआईसी कर्नाटक था, जिसने राज्य भर में शासन को सशक्त बनाने वाले अत्याधुनिक डिजिटल समाधान प्रस्तुत किए। छात्रों से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों तक, आगंतुक नागरिक सेवाओं को बदलने वाले एनआईसी के प्लेटफ़ॉर्म से जुड़े।

श्री शेट्टार ने एनआईसी स्टॉल के दौरे के दौरान कुशल, समावेशी और तकनीक-संचालित शासन प्रदान करने में इसकी भूमिका की सराहना की।

इसमें मुख्य आकर्षण बागलकोट के वरिष्ठ निदेशक (आईटी) श्री गिरियाचर वी का तकनीकी सत्र था, जिसमें उन्होंने एनआईसी की प्रमुख आईसीटी पहलों- डिजिटल स्वास्थ्य, कृषि, क्लाउड इंफ्रा और रियल-टाइम सेवा वितरण के बारे में विस्तार से बताया।

प्रदर्शित किए गए मुख्य समाधान:

- **ई-ऑफिस** - सरकारी विभागों के लिए पेपरलेस वर्कफ़्लो
- **ई-हॉस्पिटल** - अपॉइंटमेंट और स्वास्थ्य रिकॉर्ड तक डिजिटल पहुँच
- **फ्रूट्स** - किसान पंजीकरण और कृषि-लाभ के लिए एकीकृत प्लेटफ़ॉर्म
- **सर्विसप्लस और मोबाइल ऐप** - सार्वजनिक सेवा तक पहुँच को सरल बनाना
- **शिकायत निवारण प्रणाली** - पारदर्शिता और जवाबदेही को मज़बूत करना
- **प्रत्येक समाधान NIC के मूल मूल्यों को दर्शाता है:** समावेशिता, नवाचार और प्रभाव

एनआईसी की उपस्थिति ने कर्नाटक की डिजिटल रीढ़ के रूप में इसकी भूमिका की पुष्टि की, बेलगावी से लेकर राज्य के हर कोने तक परिवर्तन को आगे बढ़ाया। जैसे-जैसे कर्नाटक प्रौद्योगिकी-संचालित भविष्य की ओर बढ़ रहा है, एनआईसी दृढ़ता से खड़ा है - स्मार्ट, त्वरित और नागरिक-प्रथम शासन को सक्षम बना रहा है।

- हेमेंद्र कुमार सैनी, एनआईसी-मुख्यालय

श्री वासप्पनवारा गिरियाचर जिला सूचना-विज्ञान अधिकारी बागलकोट ने कर्नाटक में एनआईसी की प्रमुख आईसीटी पहलों पर एक जानकारी पूर्ण प्रस्तुति दी।

माननीय प्रशासक केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ ने एसएमआईएस के माध्यम से 'कैशलेस कैंपस' पहल शुरू की

पंजाब के माननीय राज्यपाल और यूटी चंडीगढ़ के प्रशासक, श्री गुलाब चंद कटारिया ने 11 जून 2025 को स्कूल प्रबंधन सूचना प्रणाली (एसएमआईएस) के तहत 'कैशलेस कैंपस' पहल का शुभारंभ किया।

राज्यपाल ने इस पहल को शिक्षा में डिजिटल शासन की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम बताया, जो स्कूलों में वित्तीय लेनदेन में पारदर्शिता, सुरक्षा और सरलता को बढ़ावा देगा।

एनआईसी यूटी चंडीगढ़ द्वारा विकसित 'कैशलेस कैंपस' पहल का नेतृत्व श्री नितिन, वैज्ञानिक-एफ ने श्री रमेश कुमार गुप्ता, डीडीजी और एसआईओ, यूटी चंडीगढ़ के मार्गदर्शन में किया। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य छात्रों के बीच डिजिटल साक्षरता को मजबूत करना है और साथ ही 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्रीय दृष्टिकोण में योगदान देना है।

इस अवसर पर उपस्थित प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों में यूटी चंडीगढ़ के मुख्य सचिव श्री राजीव वर्मा, शिक्षा सचिव श्रीमती प्रेरणा पुरी, स्कूल शिक्षा निदेशक श्री हरसुहिंदर पाल सिंह बराड़, एनआईसी यूटी चंडीगढ़ के डीडीजी और एसआईओ श्री रमेश कुमार गुप्ता और एनआईसी यूटी चंडीगढ़ के वैज्ञानिक-एफ श्री नितिन शामिल थे।

स्कूल प्रबंधन सूचना प्रणाली (एसएमआईएस) एक व्यापक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में शैक्षणिक संस्थानों के प्रशासनिक, शैक्षणिक और वित्तीय संचालन को सुव्यवस्थित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

एसएमआईएस की मुख्य विशेषताएं:

- भूमिका-आधारित पहुँच के साथ एकल बिंदु प्रविष्टि पोर्टल
- छात्र, शिक्षक और स्कूल डेटा की स्वचालित पॉपुलेशन के लिए यूडीआईएसई+ के साथ एपीआई एकीकरण
- कक्षा शिक्षकों और स्कूलों द्वारा डिजिटल उपस्थिति दर्ज करना
- अनुपस्थित छात्रों के अभिभावकों को स्वचालित एसएमएस अलर्ट

श्री रमेश कुमार गुप्ता, उपमहानिदेशक और राज्य सूचना-विज्ञान अधिकारी एनआईसी, यूटी चंडीगढ़ को मंच पर सम्मानित किया गया।

- छात्र लॉगिन के माध्यम से ऑनलाइन रिपोर्ट कार्ड प्राप्त करना
- ऑनलाइन शुल्क भुगतान प्रणाली, पीएफएमएस के साथ एकीकृत और संबंधित डीडीओ और पीएओ खातों से जुड़ी हुई
- शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए स्टाफ पंजीकरण और स्वीकृत पद प्रबंधन

यह पहल शिक्षा में डिजिटल परिवर्तन के प्रति एनआईसी की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जो यूटी चंडीगढ़ के स्कूल पारिस्थितिकी तंत्र में कुशल प्रशासन, वास्तविक समय डेटा तक पहुंच और नागरिक-केंद्रित सेवाएं सुनिश्चित करती है।

- प्रतिभा सिंह, चंडीगढ़

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने एचएमएस एमआईएस पोर्टल लॉन्च किया और आदिवासी छात्रावासों के लिए डीबीटी को हरी झंडी दिखाई

डिजिटल परिवर्तन और समावेशी शासन की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में, छत्तीसगढ़ सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने 10 जून 2025 को छात्रावास प्रबंधन प्रणाली (एचएमएस) एमआईएस पोर्टल का आधिकारिक रूप से शुभारंभ किया और आदिवासी छात्रों की सेवा करने वाले छात्रावासों और आश्रमों के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) तंत्र की शुरुआत की। यह कार्यक्रम श्री रामविचार नेताम, माननीय मंत्री और श्री सोनमणि बोरा, प्रमुख सचिव, एसटी और एससी विकास, ओबीसी और अल्पसंख्यक विकास विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित किया गया।

एनआईसी, छत्तीसगढ़ द्वारा डिजाइन और विकसित, एचएमएस एमआईएस पोर्टल राज्य के सभी जिलों में छात्रावासों और आश्रमों के प्रबंधन के लिए एक व्यापक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसका उद्देश्य छात्र कल्याण सेवाओं के वितरण में पारदर्शिता, दक्षता और पहुंच को बढ़ाना है।

पोर्टल की एक प्रमुख विशेषता प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) का एकीकरण है, जो आदिवासी छात्रों को आवास प्रदान करने वाले छात्रावासों और आश्रमों को समय पर और जवाबदेह निधि वितरण सुनिश्चित करता है। मैन्युअल बाधाओं को दूर करके और वास्तविक समय की निगरानी को सक्षम करके, यह प्रणाली प्रशासकों को बेहतर निगरानी के साथ सशक्त बनाती है और बेहतर सेवा वितरण का समर्थन करती है।

इस दोहरे लॉन्च के साथ, छत्तीसगढ़ सरकार आदिवासी समुदायों के कल्याण के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने और पारदर्शी और कुशल तरीके से लाभ के अंतिम छोर तक वितरण सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करती है।

अधिक जानकारी के लिए, देखें: https://hmstribal.cg.nic.in

- सत्येश कुमार शर्मा, छत्तीसगढ़

नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व ऑनलाइन परमिट पोर्टल का शुभारंभ

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी), उत्तराखंड द्वारा स्थायी इकोटूरिज्म और डिजिटल सुविधा को बढ़ाने की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व (एनडीबीआर) के भीतर स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, फूलों की घाटी के लिए ऑनलाइन परमिट बुकिंग प्रणाली को सफलतापूर्वक विकसित और लॉन्च किया गया है।

इस प्रणाली की संकल्पना और विकास एनआईसी उत्तराखंड द्वारा श्री संजय गुप्ता, राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी और वरिष्ठ तकनीकी निदेशक के मार्गदर्शन में किया गया था। कोर टीम में श्री अरुण शर्मा, निदेशक (आईटी) और परियोजना समन्वयक, और श्री शक्ति प्रसाद रतूड़ी, संयुक्त निदेशक (आईटी) शामिल थे, जिन्होंने सामूहिक रूप से एक सुरक्षित, स्केलेबल और उपयोगकर्ता-केंद्रित समाधान सुनिश्चित किया।

मुख्य विशेषताएं:

- **पूरी तरह से कॉन्फ़िगर करने योग्य फ्रेमवर्क** - विभिन्न बायोस्फीयर रिजर्व और ट्रेकिंग परमिट सिस्टम के लिए अनुकूलनीय
- **स्व-सेवा डैशबोर्ड** - प्रशासकों और उपयोगकर्ताओं के लिए वास्तविक समय विश्लेषण
- **उपयोगकर्ता-केंद्रित डिज़ाइन** - सहज नेविगेशन के लिए उन्नत यू आई/यू एक्स
- **एकीकृत सूचना केंद्र** - जैव विविधता डेटा, आगंतुक दिशा-निर्देश और ट्रेकिंग विवरण तक केंद्रीकृत पहुंच
- **सरलीकृत बुकिंग प्रवाह** - उपयोग में आसानी के लिए सुव्यवस्थित चार-चरणीय प्रक्रिया

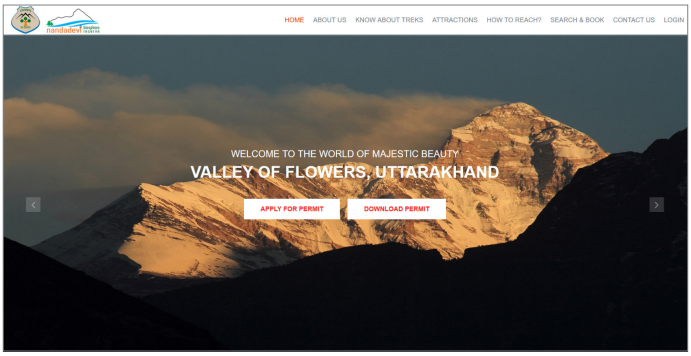

इस प्रणाली को दोहराव को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है, जो इसे अन्य बायोस्फीयर रिजर्व और इको-टूरिज्म गंतव्यों के लिए एक स्केलेबल मॉडल बनाता है, जिसका उद्देश्य उनके परमिट और आगंतुक प्रबंधन प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाना है। यह पहल प्रौद्योगिकी-संचालित शासन के माध्यम से पर्यावरण के प्रति जागरूक पर्यटन को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

- चंचल गोयल, उत्तराखंड

असम ने स्मार्ट पीडीएस वितरण में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया

भारत के सार्वजनिक वितरण सुधारों के लिए एक निर्णायक क्षण में, असम ने एक ही दिन में 35 लाख से अधिक पीडीएस लेन-देन दर्ज करके एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है - किसी भी अखिल भारतीय पीडीएस पहल के तहत अब तक का सबसे अधिक रिकॉर्ड। यह ऐतिहासिक उपलब्धि जून 2025 में राज्य के मेगा प्री-मानसून वितरण अभियान के दौरान हासिल की गई।

इस सफलता के मूल में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा विकसित और लागू की गई स्मार्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली (स्मार्ट पीडीएस) है। इस प्रणाली ने असम के सभी जिलों में निर्बाध सेवा वितरण सुनिश्चित करते हुए औसत सिस्टम लोड का तीन गुना प्रबंधन करके असाधारण लचीलापन और मापनीयता का प्रदर्शन किया।

मुख्य विशेषताएं:

- **मजबूत लोड प्रबंधन:** स्मार्ट पीडीएस बुनियादी ढांचे ने बिना किसी सेवा व्यवधान के डिजिटल लेनदेन में तीन गुना वृद्धि को कुशलतापूर्वक संभाला, जिससे असम की उच्च-मात्रा वाली सार्वजनिक सेवा संचालन के लिए तैयारी की पुष्टि हुई।
- **व्यापक राज्यव्यापी रोलआउट:** राशन वितरण अभियान सभी 35 जिलों में विस्तारित हुआ, जिसमें ग्रामीण और शहरी दोनों आबादी शामिल थी और मानसून के मौसम से पहले निर्बाध खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की गई।
- **प्रौद्योगिकी-संचालित वितरण:** राज्य भर में 15,000 से अधिक उचित मूल्य की दुकानें इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ़ सेल (ईपीओएस) उपकरणों के माध्यम से संचालित हुईं, जिससे वास्तविक समय में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण संभव हुआ और चोरी में काफी कमी आई।
- **एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ओएनओआरसी) सक्षम:** ओएनओआरसी योजना असम में पूरी तरह कार्यात्मक थी, जिससे लाभार्थी - प्रवासी श्रमिकों और शहरी गरीबों सहित - राज्य के किसी भी स्थान से अपने अधिकारों का उपयोग कर सकते थे।

यह उपलब्धि कल्याणकारी योजनाओं के प्रशासन में एक आदर्श बदलाव को दर्शाती है, जिसमें प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचे और उत्तरदायी शासन का सम्मिश्रण है। असम के खाद्य, नागरिक आपूर्ति

खुरखुरी में पीडीएस लाभार्थी

और उपभोक्ता मामले विभाग ने इसे "डिजिटल सशक्तिकरण के माध्यम से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में एक निर्णायक उछाल" कहा।

एनआईसी के अधिकारियों ने कहा कि असम की यह उपलब्धि स्मार्ट पीडीएस की परिवर्तनकारी क्षमता को रेखांकित करती है, उन्होंने कहा:

"यह मील का पत्थर इस बात का प्रमाण है कि जब स्केलेबल प्रौद्योगिकी समाधान प्रशासनिक दृष्टि के साथ संरेखित होते हैं तो क्या संभव है। असम ने राष्ट्र के लिए एक नया मानदंड स्थापित किया है।"

इस उपलब्धि के साथ, असम ने न केवल मानसून-पूर्व खाद्य वितरण की तत्काल चुनौती का सामना किया है, बल्कि तकनीक-सक्षम, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित सार्वजनिक सेवा वितरण के लिए एक राष्ट्रीय मॉडल के रूप में भी उभरा है।

- मैत्रेयी सरमा, असम

देशभर में ई-शासन गतिविधियों के बारे मे नवीनतम व अद्यतन समाचारों व सूचना के लिये News पर जाये https://informatics.nic.in/news